के गई है अलग-अलग प्राथमिक नियुक्ति किये जाये। (iii)

विश्वविद्यालयी परीक्षाएं सम्बन्धी सुझाव :-

1 निबन्धात्मक परीक्षाओं में सुधार किया जाये और साथ ही वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं शुरू की जाये।

2. कृपांक देने की प्रणाली समाप्त की जाये

3. प्रायोगिक विषयों की परीक्षा में लिखित, प्रायोगिक और मौखिक तीनों प्रकार की परीक्षाएं हों।

4. स्नातक कोर्स के तृतीय वर्ष और परास्नातक के द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण होने पर क्रमशः तीनों और दोनों वर्षों के संयुक्त प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान की जाये प्रथम श्रेणी 75%, द्वितीय श्रेणी 55% तथा 40% ऊपर तृतीय श्रेणी हो।

स्त्री शिक्षा सम्बन्धी सुझाव :-

1. स्त्री शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्हें सुमाता और सुगृहणी बनाना होना चाहिए।

2. स्त्रियों की शिक्षा के पाठ्यक्रम में गृह प्रबंध गृह अर्थशास्त्र और पोषण की शिक्षा को स्थान मिलना चाहिए। उच्च शिक्षा स्तर पर सह शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।

धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा सम्बन्धी शिक्षा :-

1. धार्मिक शिक्षा, प्राथमिक, माध्यमिक और स्नातक स्तर पर अनिवार्य होनी चाहिए।

2. प्रत्येक शिक्षा संस्था का प्रारम्भ प्रतिदिन मौन उपासना से होना चाहिए।

A Quality Product from Chitra

मूल्यांकन :—

गुण :— 1. विश्वविद्यालयी शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया।

2. विश्वविद्यालय आयोग का गठन।
3. विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध महाविद्यालयों पर अंकुश।
4. तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम और सामान्य शिक्षा अनिवार्य।
5. शिक्षण स्तर में सुधार।
6. शिक्षकों के वेतनमान और सेवा शर्तों में सुधार।
7. पदोन्नति के लिए योग्यता एवं शोध कार्यों का महत्व।
8. विभिन्न प्रकार की व्यावहारिक एवं तकनीकी शिक्षा को प्रोत्साहन।
9. विश्वविद्यालयी परीक्षा में सुधार के रचनात्मक सुझाव।

दोष :— 1. धार्मिक शिक्षा अनिवार्य।

2. शिक्षकों के वेतनमान में भेदभाव।
3. स्त्री शिक्षा के संदर्भ में संकुचित दृष्टिकोण
4. ग्रामीण विश्वविद्यालयों का सुझाव एवं अव्यवहारिक।
5. शिक्षा के माध्यम के बारे में अस्पष्ट सुझाव।

आयोग की सिफारिशों का प्रभाव :—

1. इस आयोग के सुझाव पर कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, विधि और शिक्षक प्रशिक्षण के स्वतंत्र महाविद्यालयों की स्थापना हुई।
2. विश्वविद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षकों के वेतनमानों में वृद्धि की गई और उनकी सेवा शर्तों में सुधार किया।
3. उच्च विषयों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था प्रादेशिक आधारों में शुरू की गई।
4. इस आयोग के सुझाव पर देश में ग्रामीण की आवश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयों की स्थापना में तेजी आयी। सरकार ने 1954 में केन्द्र में ग्रामीण उच्च शिक्षा की समिति की स्थापना की और इसे ग्रामीण शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा।

A Quality Product from Chitra